KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

Regd. Off.: 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara, 311001 Rajasthan
Website- www.krishnaphoschem.com, Email- secretarial@krishnaphoschem.com
CIN:L24124RJ2004PLC019288 | Ph.: 01482-237104, Fax: 01482-239638

OSTWAL

Unaudited Financial Results For the Quarter & Nine Months Ended 31st December 2019

[Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine Month Ended		Year ended
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
1	Total Income From Operation	4646.37	4262.44	4052.34	13844.94	11712.73	15300.88
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, and Exceptional items)	717.24	442.41	456.64	1791.63	1850.12	2001.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	717.24	442.41	456.64	1791.63	1850.12	2001.32
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	597.07	294.36	297.17	1321.19	1362.78	1441.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	597.07	294.36	297.17	1321.19	1362.78	1441.37
6	Equity Share Capital	2490.00	2490.00	2490.00	2490.00	2490.00	2490.00
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balances Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	5987.44
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)						
	1. Basic	2.40	2.35	1.19	5.31	5.47	5.79
	2. Diluted	2.40	2.35	1.19	5.31	5.47	5.79

Note :

a. The above results were reviewed by the Audit Committee of the Board and thereafter were approved by the Board of Directors in their meeting held on February,03,2020.

b. The above financial results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('IND AS') as prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read ith relevant rules issued there under.

c. The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and Nine Months ended 31st December 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.nseindia.com and Company's websites www.krishnaphoschem.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Sunil Kothari)
Whole Time Director & CFO
DIN 02056569

Dated: 03-02-2020
Place: Bhilwara

For Your Information...

Mathematics ranking of school students

1. Singapore
2. Hong Kong
3. Macau
5. Japan
6. China
7. South Korea
10. Canada
16. Germany
23. Australia
25. Russia
26. France
27. UK
30. Italy
32. Spain
39. US
40. Israel
47. UAE
49. Turkey
56. Mexico
63. Indonesia
65. Brazil

Source: PISA

Compiled by Nafanuksan Research

विचार सागर

''आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है।''

- पी.सी. वर्मा

''प्रेम से देखने पर यहां सब ओर स्वर्ग ही स्वर्ग और घृणा से देखने पर नरक ही नरक दिखाई पड़ेगा।''

- के.आर. कमलेश

Thoughts of the time

When a deep injury is done to us, we never recover until we forgive.

- Alan Paton

राजस्थानी कहावत

काल री काल अर आज री आज

कल की कल और आज की आज

- कल की कल देखी जायेगी।
- आज अपना है, कल का क्या भरोसा।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

बाजार

बीएसई सेन्सेक्स	39735	-987
एनएसई निफ्टी	11661	-300
इंडिया विक्स	16.36	0.56
एमसीएक्स कॉमडेक्स	10105	-15
डॉलर (रुपये में)	71.34	-0.14
यूरो (रुपये में)	79.15	-0.36
कच्चा तेल (डालर/बैरल)	51.56	-0.58
लंदन ब्रेंट क्रूड (डालर/बैरल)	56.62	-0.71
एल्यूमिनियम (डॉलर/टन)	1709	-13
तांबा (डॉलर/टन)	5570	-51
निकल (डॉलर/टन)	12675	-110
टिन (डॉलर/टन)	16275	400
जिंक (डॉलर/टन)	2219	-16
सोना (डॉलर /औंस)	1589	10
सोना (MCX, रु. प्रति 10 ग्राम)	41248	248
चांदी (MCX, रु. प्रति किलो)	47118	129

यह भाव शाम 6.00 बजे तक के हैं।

मंगलवार के चौघड़िए

सम्वत् 2076 माघ सुदी दशमी
राहुकाल : अपराह्न 3:00 से 4:30 बजे तक
सूर्योदय: 7.15 बजे और सूर्यास्त : 6.07 बजे

प्रातः 7.15 से 8.37	रोग
8.37 से 9.59	उद्वेग
9.59 से 11.20	चर
11.20 से 12.41	लाभ
12.41 से 2.02	अमृत
2.02 से 3.23	काल
3.23 से 4.44	शुभ
4.44 से सूर्यास्त 6.07	रोग
रात्रि 6.07 से 7.46	काल
7.46 से 9.24	लाभ
9.24 से 11.02	उद्वेग

आप ही तय कीजिए नई टैक्स स्कीम से फायदा होगा या नुकसान

नयी दिल्ली/पीटीआई

सालाना 13 लाख रुपये से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं 12 लाख रुपये से कम वेतन और दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले वेतनभोगी तबके के लिये पुरानी कर व्यवस्था ही फायदेमंद होगी। उन्हें पुरानी व्यवस्था में कम कर देना होगा।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 5.78 करोड़ करदाताओं में से 5.3 करोड़ के करीब करदाता दो लाख रुपये से कम की कर छूट अथवा कटौती का दावा करते हैं। यह छूट मानक कटौती,

भविष्य निधि, आवास रिण के ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर मिलने वाली कटौती के तहत उपलब्ध होती है।

इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि वास्तव में 90 प्रतिशत के करीब व्यक्तिगत करदाता दो लाख रुपये से कम कर कटौती का दावा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020- 21 का आम बजट पेश करते हुये आयकर दाताओं क लिये नई सात स्लैब वाली कर व्यवस्था का विकल्प दिया है। नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को वर्तमान में उपलब्ध कई रियायतें और छूट उपलब्ध नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि सालाना 13 लाख रुपये अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नये कर ढांचे में 1.43 लाख रुपये का कर देना होगा जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपये की कर देनदारी बनेगी। इस प्रकार नई व्यवस्था में उसे 5,200 रुपये की बचत होगी। वहीं 14 लाख रुपये सालाना वेतन पर नई व्यवस्था में 10,400 रुपये और 15 लाख तथा इससे अधिक के वेतन पर 15,600 रुपये की बचत होगी। इस गणना में व्यक्तियों द्वारा दो लाख रुपये तक की विभिन्न बचतों पर कटौती का दावा भी शामिल किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि गैर- वेतनभोगी व्यक्तियों में जिन्हें 50 हजार रुपये की मानक कटौती नहीं मिलती है। उनमें सालाना 9.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले और डेढ लाख रुपये तक कटौती का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये नई कर व्यवस्था में 5,200 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये कर ढांचे में मौजूदा 5%, 20% और 30% आयकर दरों के अलावा 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के तीन नये स्लैब जोड़े हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में ढाई लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखा गया है। हालांकि, वित्त मंत्री का कहना है कि दोनों व्यवस्थाओं में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय होने पर कर नहीं देना होगा।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के संशोधित लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेंगे

नयी दिल्ली/पीटीआई। प्रत्यक्ष कर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर वसूली के संशोधित अनुमानों को प्राप्त किए जाने का भरोसा जताया है। उसका कहाना है कि बजट में चालू वित्त वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को घटाकर 11.80 लाख करोड़ रुपये किए जाने का फैसला विभिन्न आर्थिक कारकों के व्यावहारिक आकलन के बाद किया गया है। गौरतलब है कि पिछले बजट में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (व्यक्तिगत आयकर, कंपनी कर और अन्य) का लक्ष्य 13.35 लाख करोड़ रुपय रखा गया था जिसे संशोधित बजट अनुमान में कम कर 12 लाख करोड़ रुपये से नीचे ला दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने शनिवार को पेश 2020-21 के आम बजट के बाद पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर वसूल संबंधी , 'पहले के अनुमानों को नए बजट में संशोधित किया गया है। अब हमारा लक्ष्य 11.80 लाख करोड़ रुपये का है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे।''

लक्ष्य को संशोधित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा, ''यह एक उचित आकलन है, जो हासिल होने योग्य है। इसकी एक और वजह है कि हमारा काफी राजस्व चला गया है।'' मोदी ने कहा कि बड़ी मात्रा में रिफंड और कंपनी कर में कटौती से राजस्व प्रभावित हुआ है। सीबीडीटी आयकर विभाग का नीति बनाने वाला निकाय है।

जीएसटी : 1200 करोड़ रुपये के फर्जी बिल उपयोग करने को लेकर एक व्यक्ति गिरफ्तार

नयी दिल्ली/एजेंसी। दिल्ली में माल एवं सेवाकर अधिकारियों ने कहा है कि कर लाभ लेने के लिये 1,200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के फर्जी बिल का कथित रूप से उपयोग करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम दिल्ली आयुक्त कार्यालय के सोमवार के एक बयान के अनुसार हाल में गिरफ्तार दया शंकर कुशवाहा ने सरकार के साथ धोखाधड़ी के लिये 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया।

बयान के अनुसार, ''केंद्रीय कर से जुड़ी कर चोरी निरोधक इकाई पश्चिम दिल्ली आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने 124 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े 1,200 करोड़ रुपये के फर्जी बिल काटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया गया था।'' इस गोरखधंधे में वस्तुओं की खरीद के फर्जी बिल काटे गए ताकि वे उसके अधार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकें जबकि उन्होंने वास्तव में एक नग भी माल प्राप्त नहीं किया था। बयान में कहा गया है, ''खरीदारों को फर्जी बिल जारी किये गये। उन लोगों ने बिना कोई वस्तु लिये धोखाधड़ी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। दया शंकर कुशवाहा ने जांचकर्ताओं के समक्ष स्वीकार किया कि बिलों के एवज में कोई वस्तु नहीं ली गयी...।''

जांच में पाया गया कि कुशवाहा ने धोखाधड़ी कर दो अलग-अलग पैन कार्ड प्राप्त किये। इसमें जो फोटो उपयोग किये गये, उसे फोटोशॉप के जरिये यानी डिजिटल रूप से कुछ बदलाव किये गये थे। उसके जरिये उसने 14 कंपनियां बनायीं। शेष 35 कंपनियां गरीब लोगों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) दस्तावेज चुराकर 35 कंपनियां बनायी। पश्चिम दिल्ली आयुक्त कार्यालय के बयान में अनुसार, ''कुल मिलाकर आरोपी ने 297 कंपनियां बनायीं। इनमें से कुछ का उपयोग बैंक लेन-देन के लिये किया गया...।'' शुरूआती जांच में 60 से अधिक बैंक खातों का पता चला है। इन खातों का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह लेन-देन में किया जा रहा था ताकि वे सही लगे।

लघु बचत ब्याज दरों में अगली तिमाही में संशोधन संभव

नयी दिल्ली/पीटीआई। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने अगली तिमाही में लघु बचत ब्याज दरों में संशोधन के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि इसे बाजार दरों के अनुरूप संतुलित बनाया जा सकता है। इससे नीतिगत दरों के लाभ को तेजी से आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है। बैंक जमा दरों में नरमी के बावजूद चालू तिमाही में सरकार ने लोक भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने से दूरी बनाए रखी।

चक्रवर्ती ने कहा, ''देश में हमारे पास वर्तमान में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये लघु बचत योजनाओं में और करीब 114 लाख करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में हैं। इससे बैंकों की देनदारी इन 12 लाख करोड़ रुपये से प्रभावित हो रही है।'' उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसी स्थिति है जब कोई कमजोर इंसान किसी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को नियंत्रित करने लगे। कमोबेश लघु बचतों की ब्याज दर का कुछ जुड़ा बाजार दरों से होना चाहिए जो बड़े स्तर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्रभावित होती हैं।

चक्रवर्ती ने कहा कि श्यामला गोपीनाथ समिति की रपट को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ब्याज दरों को बाजार दरों से जोड़ने का काम चल रहा है। 'इस तिमाही के लिए ब्याज दरों का इंतजार कीजिए, यह आपको लगभग-लगभग अच्छे संकेत देगा।''

उन्होंने कहा कि अभी कुछ सांकेतिक मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा रहा है। बैंकों का कहना है कि लघु बचतों पर ऊंचे ब्याज से उन्हें अपनी जमा ब्याज दरों में कटौती करने में दिक्कत आ रही है। एक साल की परिपक्वता अवधि के लिए बैंकों की जमा ब्याज दर और लघु बचत दरों में करीब एक प्रतिशत का अंतर है। उन्होंने कहा कि भले सरकार लघु बचत योजनाओं पर निर्भर नहीं है, लेकिन सरकार का इन योजनाओं को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।

राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाने की स्थिति में सरकार के बाजार से अतिरिक्त धन जुटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस साल सरकार बाजार से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं उठाएगी और ना ही सरकार की घाटे का मौद्रीकरण करने की कोई योजना है। उल्लेखनीय है कि राजस्व संग्रह में कमी के चलते सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.8 प्रतिशत होने का अनुमान जताया है। यह बजट अनुमान 3.3 प्रतिशत से अधिक है।

देश की विनिर्माण गतिविधियां आठ साल के उच्च स्तर पर

नयी दिल्ली/पीटीआई। बाजार मांग में सुधार का असर दिखना शुरू हो गया है। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी में देश की विनिर्माण गतिविधियां आठ साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गयी हैं। इससे उत्पादन और रोजगार गतिविधियों में भी बेहतरी दिख रही है। कंपनियों के खरीद प्रबंधकों (परचेजिंग मैनेजर) के बीच किए बीच किए जाने वाले मासिक सर्वेक्षण आईएचएस मार्किट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स (विनिर्माण पीएमआई) जनवरी में 55.3 अंक रहा है। यह 2012 से 2020 की अवधि में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले दिसंबर में यह 52.7 अंक था। जबकि साल भर पहले जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 53.9 अंक था।

यह लगातार 30वां महीना है जब विनिर्माण पीएमआई 50 अंक से ऊपर रहा है। पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार जबकि 50 अंक से नीचे रहना संकुचन के रुख को दर्शाता है। जनवरी में विनिर्माण पीएमआई के उच्च स्तर पर रहने की अहम वजह मांग में सुधार होना है। इसकी वजह से नए ऑर्डर मिलने, उत्पादन, निर्यात और विनिर्माण के लिए खरीदारी और रोजगार में बढ़त देखी गयी है। साथ ही कारोबारी धारणा में भी सुधार हुआ है। आईएचएस मार्किट में प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियाना डि लिमा ने कहा, '' जनवरी में देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी है। परिचालनात्मक परिस्थियों में जिस गति से सुधार देखा गया है, ऐसा आठ साल की अवधि में नहीं देखा गया।'' सर्वेक्षण में कंपनियों ने माना कि नए ऑर्डर मिलने में जो मजबूती देखी गयी है वह पांच साल की अवधि में नहीं देखी गयी। इसकी प्रमुख वजह मांग का बढ़ना और ग्राहक की जरूरतों का सुधार होना है। कंपनियों की कुल बिक्री में विदेशी बाजारों से बढ़ी मांग की अहम भूमिका है।

पृष्ठ एक से जारी...

कोरोना...

रात तक इससे प्रभावित 17,000 से अधिक लोगों की पहचान की गयी है। इसके तेजी से हो रहे प्रसार का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बाजार में निवेशकों के बीच इसे लेकर काफी डर है।

चीनी नव वर्ष की सप्ताह भर लंबी छुट्टी के बाद शंघाई शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दिखी। शांघाई कंपोजिट शेयर सूचकांक आठ प्रतिशत तक गिरकर बंद हुआ। यह अगस्त 2015 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। शंघाई कंपोजिट 229.92 अंक यानी 7.72 प्रतिशत घटकर 2,746.61 अंक पर बंद हुआ। छुट्टियां शुरू होने से पहले बाजार 23 जनवरी को खुला था और उस दिन शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.8 प्रतिशत गिरा था। चीन सरकार 2008 में वैश्विक मंदी और 2002-2003 में सार्स बीमारी के फैलने के बाद बाजारों में उथल-पुथल को रोकने के दौरान भी वह इस तरह के कदम उठा चुकी है। चीन की अधिकतर बड़ी कंपनियां और वित्तीय संस्थान सरकार के नियंत्रण में हैं। रविवार को चीन के केंद्रीय बैंक ने बाजार में 1,200 अरब युआन (173 अरब डॉलर) की अतिरिक्त नकद राशि झोंकने की योजना की घोषणा की। यह पैसा बांड की ताकि बाजार में नकदी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। सोमवार को कई क्षेत्रों की कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गयी। चीन की दवा कंपनियों के शेयर शुरुआती कारोबार में 10 प्रतिशत तक गिर गए। इसी तरह चीन के छोटे बाजारों का सूचकांक शेनझेन कंपोजिट इंडेक्स 8.41 प्रतिशत यानी 147.81 अंक गिरकर 1,609 अंक पर बंद हुआ। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान शहर में सामने आया इसके फैलने से चीन एवं आसपास के क्षेत्रीय पर्यटन और वैश्विक वृद्धि पर असर पड़ रहा है।

पिछले...

घरेलू उत्पाद में पिछले साल 1.2 प्रतिशत की गिरावट आयी। वहीं चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में 2.9 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक

Name	Last Trade	Change (%)
SGX NIFTY	11,703.50	-2.37
NIKKEI 225	22,971.94	-1.01
STRAITS TIMES	3,116.31	-1.19
HANG SENG	26,356.98	0.17
TAIWAN WEIGHTED	11,354.92	-1.22
KOSPI	2,118.88	-0.01
Nasdaq	-	-
S&P	-	-
DAX*	12990.83	+ 0.07
CAC 40*	5808.50	+ 0.04
FTSE 100*	7309.36	+ 0.32

*(*यह आंकड़े शाम 06:00 बजे तक के हैं)*

रणनीतिक भंडारगृहों की कच्चे तेल की बिक्री आय को बजट में दी गई कर छूट

नयी दिल्ली/पीटीआई। विदेशी कंपनियों को भारत के रणनीतिक तेल भंडार में रखे गये तेल की बिक्री पर कर छूट देने के बाद आम बजट 2020-21 में भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भी रखे गये कच्चे तेल की खरीद- बिक्री से होने वाली आय पर कर छूट दी गई है। सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में रखे गये कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय पर 2017 में कर छूट दे दी थी। बजट दस्तावेज के अनुसार, आईएसपीआरएल को देश के रणनीतिक भंडारगृहां में रखे गये कच्चा तेल की बिक्री पर आयकर से छूट दी गयी है। हालांकि, इसके साथ ही यह शर्त है कि कंपनी को तीन साल के भीतर भंडार में वापस उतना ही कच्चा तेल भरना होगा। कंपनी के लिये नयी व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017- 18 के बजट में रणनीतिक तेल भंडार में भंडारण क्षमता की बुकिंग करने वाली कंपनियों के आय को कर से छूट दे दी थी।

राष्ट्रीय आरंभिक निवेश कोष के लिये दिशानिर्देश तय किये जा रहे हैं: महापात्र

नयी दिल्ली/पीटीआई। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) बजट में स्टार्ट-अप इकाइयों को पूंजीगत मदद के लिए घोषित राष्ट्रीय आरंभिक-निवेश कोष के लिये दिशानिर्देश तय कर रहा है। डीपीआईआईटी के सचिव गुरुदास महापात्र ने कहा कि अधिकांश स्टार्टअप इकाइयों को अपने कारोबार की अवधारणा तय किये जाने से लेकर उस अवधारणा की पुष्टि होने के काल खण्ड में पैसा जुटाने में समस्या होती है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने ऐसी इकाइयों को आरंभिक अंश पूंजी देने का प्रस्ताव बजट में कर दिया है। अब डीपीआईआईटी इसके नियम निर्देश निर्धारित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्टार्ट-अप इकाइयों को कारोबार की अवधारणा के चरण से विकास के प्रारंभिक चरण के दौर में वित्तीय सहयोग के लिए आरंभिक धन उपलब्ध कराने के लिये इस कोष का प्रस्ताव किया। इसके जरिये उन्हें आरंभिक शेयर-पूंजी भी दी जा सकती है। महापात्र ने कहा, ''इस लिये अब हम एक कैबिनेट नोट भेजेंगे और यह कोष बनाएंगे तथा इसके दिशानिर्देश तय करेंगे।''

कोयला आयात आठ प्रतिशत बढ़कर 18.58 करोड़ टन

नयी दिल्ली/पीटीआई। देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर की अवधि में 7.6 प्रतिशत बढ़कर 18.58 करोड़ टन पर पहुंच गया। एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में कोयला आयात 13.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.05 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 1.81 करोड़ टन रहा था। दिसंबर में नॉन कोकिंग कोयले आयात बढ़कर 1.42 करोड़ टन रहा। यह दिसंबर, 2018 में 1.25 करोड़ टन रहा था। इसी तरह कोकिंग कोयले का आयात 44.7 लाख टन रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 37.6 लाख टन रहा था। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने कहा, ''दिसंबर में आयात गतिविधियां कुछ बढ़ीं। इसकी वजह इस्पात कीमतों में सुधार और सीमेंट और स्पॉन्ज आयरन क्षेत्रों से सतत मांग बने रहना है।'' भारत ने 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 23.52 करोड़ टन कोयले का आयात किया था।

चिकित्सकीय उपकरण उद्योग ने बजट पर जतायी निराशा, इलाज महंगा होने की जाहिर की आशंका

नयी दिल्ली/पीटीआई। चिकित्सा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन 'मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' ने कहा कि चिकित्सकीय उपकरणों पर उपकर लगाने से आयातित उत्पादों की लागत बढ़ेगी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र महंगा होगा। संगठन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मूल सिद्धांत के प्रतिकूल है। संगठन के निदेशक संजय भूटानी ने एक बयान में कहा, ''बजट में चिकित्सकीय उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क पर पांच प्रतिशत का उपकर लगाया है। इससे आयातित चिकित्सकीय उपकरणों की लागत बढ़ेगी। अंततः इस बढ़ी लागत का बोझ मरीजों पर पड़ेगा और इलाज महंगा होगा।'' उन्होंने कहा कि यह पीछे खींचने वाला कदम है और यह उन वैश्विक कंपनियों के खिलाफ है जो देश में गंभीर चिकित्सा के 80 प्रतिशत से अधिक उपकरण उपलब्ध कराते हैं। इसके कारण मरीजों के समक्ष तस्करी के ऐसे सस्ते उत्पादों का भी जोखिम बढ़ता है जो कम शुल्क वाले पड़ोसी देशों से अवैध तरीके से आते हैं और जिनके साथ सर्विस या वैध गारंटी नहीं होती है।

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
वेबसाईट: www.shrikalyan.com
सूचना

कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड
OSTWAL